साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 03-09 जुलाई 2023 वर्ष-9, अंक-12

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हुआ निर्णय

किसानों को सस्ती बिजली देने सरकार 18 हजार करोड़ देगी सब्सिडी

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में निर्णय लिए गए। किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार वर्ष 2023-24 में 18 हजार करोड़ रुपए व्यय करेगी। यह राशि विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसी तरह केले की फसल को प्राकृतिक आपदा से क्षति पहुंचने पर अब दोगुनी राहत राशि दी जाएगी। किसानों की लागत कम करने के लिए सरकार 10 हार्स पावर क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 750 रुपए और 10 हार्स पावर से अधिक क्षमता के स्थायी कृषि उपभोक्ताओं को डेढ़ हजार रुपए प्रति हार्स पावर की दर से बिजली बिल लेने का निर्णय लिया है।

- केले की फसल को आपदा से क्षति पर अब दोगुना राहत राशि
- भोज वेटलैंड की भूमि पर्यावरण वानिकी वनमंडल, भोपाल को मिलेगी।
- नगरीय निकायों को विकास योजना के अंतर्गत 1,700 करोड़ मिलेंगे।
- सीप अंबर कांप्लेक्स सिंचाई परियोजना के दूसरे चरण को स्वीकृति।

50 फीसदी केले की क्षति पर दो लाख

पिछले दिनों बुरहानपुर सहित अन्य जिलों में आंधी-तूफान से केले की फसल को हुई क्षति को देखते हुए प्रति हेक्टेयर राहत राशि देने के प्रावधान में संशोधन किया गया है। अब आर्थिक अनुदान सहायता तीन के स्थान पर अधिकतम छह लाख रुपए तक दी जाएगी। 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पर दो लाख, 33 से 50 प्रतिशत क्षति पर 54 हजार और 25 से 33 प्रतिशत क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 30 हजार रुपए की सहायता मिलेगी।

नुकसान की होगी भरपाई

बिजली कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 12686 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह एक हेक्टेयर तक भूमि वाले अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के किसानों को पांच हार्स पावर क्षमता के पंप के उपयोग पर निःशुल्क बिजली देने पर 5142 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

निराश्रित शुल्क की छूट | कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन पर मंडी के साथ अब निराश्रित शुल्क से भी छूट दी जाएगी। प्रति सौ रुपए के उपार्जन पर डेढ़ रुपए मंडी और 20 पैसे निराश्रित शुल्क लिया जाता है।

मोदी कैबिनेट का तोहफा: पांच करोड़ किसानों को फायदा

गन्ने का न्यूनतम मूल्य सरकार ने किया 315 रुपए क्विंटल

-उर्वरकों को बढ़ावा देने नई योजना पीएम-प्रणाम को मंजूरी

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के गन्ना किसानों के लिए तोहफे का एलान किया है। कैबिनेट ने गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने 2023-24 सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। कैबिनेट ने चीनी सीजन 2023-24 के लिए गन्ना किसानों के लिए 315 रुपए प्रति क्विंटल के अब तक के उच्चतम उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके आश्रितों को फायदा होगा। इसके साथ-साथ चीनी मिलों और संबंधित सहायक गतिविधियों में कार्यरत पांच लाख श्रमिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। गन्ना सत्र अक्टूबर से शुरू होता है। गन्ने का न्यूनतम मूल्य 2014-15 में 210 रुपए प्रति क्विंटल था।

पीएम-प्रणाम योजना को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना पीएम-प्रणाम को मंजूरी दी। उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। इस योजना का एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को 2023-24 के बजट के दौरान किया था। योजना के तहत केंद्र राज्यों को प्रोत्साहित करेगा कि वे वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा दें और रासायनिक उर्वरकों को कम करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई राज्य 10 लाख टन पारंपरिक उर्वरक का उपयोग कर रहा है और यदि वह अपनी खपत 3 लाख टन कम कर देता है तो सब्सिडी की बचत 3,000 करोड़ होगी।

किसानों को होगा फायदा

मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश,पंजाब और हरियाणा राज्य के किसान अपनी फसल के लिए एसएपी तय करते हैं। साधारण तौर पर एसएपी का मूल्य केंद्र सरकार के एफआरपी मूल्य से अधिक होता है। ऐसे में केंद्र की ओर से एफआरपी बढ़ाने के बाद अगर राज्य सरकार ने एसएपी नहीं बढ़ाया तो इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हो पाता।

एसएपी और एफआरपी में अंतर एफआरपी सरकार की ओर से तय किया गया मूल्य है, जिस पर मिलें किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य हैं। हमेशा एफआरपी में बढ़ोतरी से देश के सभी किसानों को फायदा नहीं हो पाता। दरअसल, कुछ राज्यों में एफआरपी के अलावे गन्ने की पैदावार के लिए राज्य समर्थित मूल्य यानी एसएपी भी तय किया जाता है। जिन राज्यों में गन्ने का उत्पादन अधिक होता है, वह अपनी फसल की कीमत खुद तय करते है। इस कीमत को एसएपी कहा जाता है।

पंचायत सचिव पद पर 50 फीसदी स्थान जीआरएस के लिए आरक्षित

रोजगार सहायकों का मानदेय बढ़ाया अब 9000 की जगह 18 हजार वेतन

-रोजगार सहायकों की सेवा आसानी से समाप्त नहीं की जा सकेगी

भोपाल। जागत गांव हमार

ग्राम रोजगार सहायकों का मासिक मानदेय अब नौ हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपए मासिक किया जाएगा। पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति में 50 प्रतिशत स्थान रोजगार सहायकों के लिए आरक्षित होंगे। ग्राम रोजगार सहायकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की। सम्मेलन भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में रोजगार सहायकों की विशेष भूमिका है। कोरोना काल में भी आम जनता और अन्य प्रदेशों के श्रमिकों को राहत देने में रोजगार सहायकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया। एक समय मनरेगा से संबंधित कार्य के लिए दायित्व निभाने वाले रोजगार सहायकों ने मनरेगा के क्रियान्वयन को व्यवस्थित करने के बाद राशन कार्ड बनवाने, संबल योजना, आयुष्मान कार्ड बनवाने, राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम और लाड़ली बहना योजना से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक किया है।

अनिश्चितता खत्म

फिजिकल का डिजिटल से मेल करवाने का कार्य रोजगार सहायकों ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिंदगी से अनिश्चितता खत्म करना आवश्यक है। रोजगार सहायक मेरे लिए विशेष हैं। जिस तरह रामेश्वरम से लंका तक सेतु बंध बनाए गए थे आज रोजगार सहायक भी नल और नील जैसी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं।

यह सौगात भी दी

रोजगार सहायकों को वर्तमान में नौ हजार मासिक मानदेय दिया जाता है। अब 18 हजार देंगे। अब रोजगार सहायकों की सेवा आसानी से समाप्त नहीं की जा सकेगी। आवश्यक प्रक्रिया अपनाने के बाद ही कार्रवाई होगी। सामान्य अवकाश सहित प्रसूति अवकाश आदि की सुविधा भी मिलेगी। मातृत्व अवकाश के साथ ही पितृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा । पंचायत सचिव की नियुक्ति में 50 प्रतिशत स्थान रोजगार सहायकों के लिए सुरक्षित रहेंगे। रोजगार सहायकों को भविष्य में स्थानांतरण और नियुक्ति से संबंधित कार्यों में पंचायत सचिवों के समान ही माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक नियम बनाए जाएंगे।

यह रहे मौजूद | कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया,राज्य मंत्री राम खेलावन पटेल, सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे, रमेशचन्द्र शर्मा, मध्यप्रदेश रोजगार सहायक संगठन के अध्यक्ष रोशन सिंह परमार, संजय सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मलय श्रीवास्तव उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन संयुक्त आयुक्त मनरेगा एमएल त्यागी ने माना।

मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य शुरू, दो सप्ताह में शुरू होगी प्रक्रिया

विधानसभा चुनाव के पहले ही मध्यप्रदेश में होंगे मंडी चुनाव

जबलपुर। जागत गांव हमार

मप्र में विधानसभा चुनाव के पहले ही मंडी के चुनाव होंगे। हाई कोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में राज्य शासन ने जवाब पेश कर साफ किया कि प्रदेश में मंडी चुनाव की प्रक्रिया दो सप्ताह में शुरू कर दी जाएगी। बुधवार को शासन द्वारा पेश किए गए इस जवाब के बाद मंडी चुनाव का बिगुल तैयार हो गया है। फिलहाल, मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने जवाब को अभिलेख पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य शासन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

लगाई गई थी जनहित याचिका- जनहित याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के संयोजक मनीष शर्मा सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मंडी अधिनियम की धारा-11 में मंडी समितियों के गठन का प्रविधान है। धारा-13 में मंडी समितियों का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित किया गया है। धारा-59 में राज्य शासन को यह शक्ति दी गई है कि वह पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद एक वर्ष के लिए चुनाव आगे बढ़ा सकता है। किंतु किसी भी सूरत में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में मनमानी की जा रही है। राज्य में मंडी समिति का कार्यकाल जनवरी-2018 में समाप्त हो चुका है। जिसके बाद कार्यकाल बढ़ाया गया। इसीलिए व्यापक जनहित में हाई कोर्ट चले आए।

06 जनवरी 2019 को भंग हो गई थी समितियां

प्रदेश भर की मंडियों के चुनाव नहीं होने से इसका भार प्रशासनिक अधिकारियों के पास आ गया था। ज्ञात हो कि कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद कृषि उपज मंडियों में बनी समितियां 6 जनवरी 2019 को भंग हो गई थीं। इसके बाद मंडियों का कार्यभार प्रशासनिक अधिकारियों के पास आ गया था। अब तक प्रशासनिक अधिकारियों की ही निगरानी में प्रदेश की मंडियों में देखरेख, कामकाज और मंडियों से जुड़े निर्णय लिए जा रहे हैं।

दो बार बढ़ाया गया था कार्यकाल | उल्लेखनीय है कि 2012 में प्रदेश की मंडियों में मंडी समिति के चुनाव हुए थे। जिसके बाद 2017 में चुनाव होने थे, लेकिन मंडी समिति का कार्यकाल दो बार छह-छह माह के लिए बढ़ा दिया गया था। कार्यकाल एक साल बढ़ने के बाद वर्ष 2018 में मंडी चुनाव होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तय समय से अधिक समय बीतने के बाद भी चुनाव नहीं होने के कारण 6 जनवरी 2019 को मंडियों में बनी समितियां भंग हो गई थीं।

कृषि अधिकारियों ने किसानों को दी सलाह-सोसायटियों से खाद-बीज का उठाव करें

अप्रैल से अब तक 18 हजार 783 टन यूरिया और 10 हजार 836 टन डीएपी का विक्रय किया

हेराफेरी से सबक... उर्वरकों का एडवांस में किया स्टाक

जबलपुर। जागत गांव हमार

पिछले साल प्रकाश में आई यूरिया की हेराफेरी से सबक लेकर प्रशासन ने पहले से व्यवस्थाओं को चौकस कर रखा है। जिले में पिछले साल के मुकाबले अधिक मात्रा में भंडारण और वितरण किया जा चुका है। कृषि विभाग के अफसरों का दावा है कि जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज उपलब्ध हैं। किसानों को चाहिए कि वो समय रहते जरूरत के अनुरूप उठाव कर लें। जिले में अप्रैल से अब तक 18 हजार 783 टन यूरिया और 10 हजार 836 टन डीएपी का विक्रय किया जा चुका है, जो कि गत वर्ष के मुकाबले अधिक है।

बीते साल उजागर हुई थी गड़बड़ी- पिछले वर्ष सरकारी गोदामों का हजारों टन यूरिया प्रायवेट व्यापारियों के यहां पहुंचा दिया गया था। जब किसानों को परेशानी हुई और मामले की तह तक जाने का प्रयास किया गया, तब गड़बड़ी उजागर हुई। जिले से लेकर भोपाल तक हड़कंप रहा। खुद सीएम को इस मामले में कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देश देना पड़े। लिहाजा इस वर्ष समय रहते ही जिम्मेदारों ने खामियों की गुंजाइश को समाप्त कर रखा है। यूरिया और डीएपी के आने वाले प्रत्येक रेक पर नजर रखी जा रही है। रेक से ट्रकों में लोड होकर अन्य स्थानों को रवाना होने वाले उर्वरकों की भी ट्रेकिंग की जा रही है। जहां खाद पहुंचना है- वहां के डबल लाक केंद्रों से भी पहुंच संबंधी फीडबैक लिया जा रहा है। अफसरों का दावा है कि अब तक कहीं से गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिल पाई है।

तमाम दावे पिछले वर्ष हुए थे धराशायी

यूरिया की सप्लाई को लेकर जिला और संभाग स्तर से पिछली बार भी पूरी एहतियात के दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों की हवा कालाबाजारी करने वालों ने निकाल दी थी। इस साल भी दावे हो रहे हैं, लेकिन इन दावों की परीक्षा जुलाई और अगस्त महीने में ही हो पाएगी। जबकि यूरिया की डिमांड सबसे ज्यादा होती है।

जिले में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त है। सभी प्रकार के उर्वरकों की सप्लाई पिछले साल की तुलना में अधिक हो चुकी है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में भंडार उपलब्ध है। कहीं से भी कालाबाजारी की नौबत न आए, इस बावद नजर रखी जा रही है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खाद बीज का आवश्यकता के अनुरूप भंडारण कर लें।

- रवि आम्रवंशी, डिप्टी डायरेक्टर कृषि

5 दिवसरीय प्रशिक्षण भ्रमण पर रवाना हुए 60 किसान

बालाघाट। जागत गांव हमार

26 जून को उद्यानिकी एवं खादय प्रसंकरण विभाग म.प्र के द्वारा जिला बालाघाट से 60 प्रगतिशील कृषकों का दल, प्रदेश के बाहर 5 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण के लिए गौरीशंकर बिसेन के द्वारा कृषकों यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए, बस को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। बिसेन ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कृषकों को कृषि की आय दुगनी, उद्यानिकी की क्षेत्र संरक्षित खेती, पाली हाउस मे फूलों, सब्जी की हाईटेक खेती, फूलो व फसलों की मार्केट की जानकारी के साथ, फलों की अनेक नई प्रजाति ड्रैगन फ्रूट, अमरुद, आम अंजीर, जैविक खेती का अवलोकन कराया जाएगा और महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी, नेशनल इसन्टीट्यूट तलेगांव पूना, रूचि बायो टेक्निकल गोंदिया मे किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

फसलों में मिट्टी परीक्षण उपरान्त अनुसंशित मात्रा में उर्वकों का प्रयोग करना चाहिए

किसानों को खरीफ फसलों में अच्छे उत्पादन के लिए वैज्ञानिकों ने दी सलाह

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. एसके जाटव एवं जयपाल छिगारहा द्वारा किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई के समय उन्नत तकनीक अपनाने की सलाह दी गई।

- उड़द की पीला मौजेक प्रतिरोधक किस्में- आईपीयू 94.1, प्रताप उड़द 1, शेखर.2, शेखर.3, इंदिरा उड़द प्रथम, मुकुंदरा आदि।
- सोयाबीन की उन्नत किस्म- जेएस 95.60, जेएस 20.34, जेएस 93.05, जेएस 20.69, जेएस 20.98, आदि।
- तिल की उन्नत किस्में- टीकेजी 306, टीकेजी 308, जीटी 4, जीटी 6, आदि।
- मूंगफली की उन्नत किस्में - टीजी 37ए, जेजीएन 23, जेएल 501, जेजीएन 3, आदि।
- धान की उन्नत किस्में- जेआर 201, जेआर 81, जेआर 345, पूसा सुगंध 4, पूसा सुगंध 3, एमटीयूए आदि शामिल है।

किसान उन्नत किस्मों की बुवाई के लिए उपयोग करें

अरहर की उन्नत किस्में-पूसा अरहर 16, पूसा 33, टीजेटी 501, राजीव लोचन आदि। उन्नत किस्मों की बुवाई के लिए उपयोग करें। फसल को फफूंद जनित बीमारियों से बचाने के लिए फफूंदनाशक दवाओं जैसे ट्राईकोडर्मा विरिडी 10 मिली या विटावैक्स पॉवर 2 ग्राम प्रति किग्रा बीज की दर से बीजोपचार कर बवाई करना चाहिए। खरीफ फसलों के अधिक उत्पादन के लिए फसलों की बुवाई कतारों में करना चाहिए और फसलों में मिट्टी परीक्षण उपरान्त अनुसंशित मात्रा में उर्वकों का प्रयोग करना चाहिए। दलहनी और तिलहनी फसलों में फस्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी की जगह सिंगल

सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे फसलों को फस्फोरस के साथ सल्फर और कैल्शियम भी प्राप्त हो जाता है। फसलों में कीट-व्याधियों से बचाव के लिए म्यूरेट ऑफपोटाश का 15.20 किग्रा प्रति एकड़ का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाईयों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रति वर्ष प्रत्येक खेत में फसलें अदल,बदल कर बोना चाहिए, जिससे फसलों की पैदावार भी अच्छी होगी और कीट-व्याधियों की समस्या भी नहीं होगी। खरीफकी फसलों में नींदा की मुख्य समस्या होती है। यदि फसलों की समय पर निंदाई-गुड़ाई नहीं की जाए तो उत्पादन काफी कम हो जाता है। इसलिए खरीफ फसलों में दो बार निंदाई-गुड़ाई करना चाहिए। एक बीज बुवाई के 15.25 दिन में दूसरी बार 35.40 दिन में करना अति आवश्यक है। नींदा जितने दिन फसल के साथ रहेगा उतना ही फसल का भोजन खाकर फसल को कमजोर और उत्पादन को प्रभावित करेगा।

विदेशी बाजार कराया जाएगा उपलब्ध, -अलग से एक सेल का गठन किया गया

जीआई टैग उत्पादों की भी होगी ब्रांडिंग

खेती बनेगी लाभ का धंधा! एक जिला एक उत्पाद की ब्रांडिंग करेगी मध्यप्रदेश सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की ब्रांडिंग की जाएगी। इसके लिए अलग से एक सेल गठित किया जा रहा है। इस सेल का काम केवल ओडीओपी का प्रचार-प्रसार करना होगा और स्थानीय उत्पाद को विदेशी बाजार उपलब्ध कराने के भी प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए कुछ उत्पादों को सैंपल के तौर पर बाहर भेजा जाएगा। विदेशी बाजार में अगर इन उत्पादों में रुचि दिखाई जाती है, तो बड़ी मात्रा में इनका निर्यात किया जाएगा। डीओपी के अलावा जिला निर्यात हब (डीईएच) और रिवर्स बायर सेलर मीट के माध्यम से जीआइ टैग (जियोग्राफिकल इंडिकेशंस) उत्पादों की ब्रांडिंग भी की जाएगी।

छोटे से छोटे उत्पाद को जीआइ टैग दिलाने के होंगे प्रयास- प्रदेश से अधिकांश उत्पादों को जीआइ टैग दिलाने भी प्रयास किए जाएंगे। इसमें आदिवासियों की पारंपरिक औषधियों, खाद्यान्न और उनकी कलात्मक वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जीआइ टैग सबसे अधिक दक्षिण भारत के हैं। मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के छोटे से छोटे उत्पाद को जीआइ टैग मिले। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 21 उत्पादों को जीआइ टैग मिला है।

मुरैना	सरसों
भिंड	सरसों
ग्वालियर	सैंड स्टोन टाइल्स
श्योपुर	अमरूद
दतिया	गुड़
शिवपुरी	कपड़ा- जैकेट
गुना	धनिया
अशोक नगर	चंदेरी हैंडलूम
नीमच	धनिया
मंदसौर	लहसुन
रतलाम	नमकीन
झाबुआ	कड़कनाथ

अलीराजपुर	महुआ	बैतूल	टीक	सिवनी	सीताफल
धार	बाघ प्रिंट	नर्मदापुरम	पर्यटन	बालाघाट	चिन्नौर चावल
बड़वानी	अदरक	रायसेन	बासमती चावल	मंडला	कोदो कुटकी
आगर मालवा	संतरा	भोपाल	जरी जरदोरी पर्स	डिंडौरी	कोदो कुटकी
उज्जैन	बटिक प्रिंट			जबलपुर	मटर
इंदौर	आलू	विदिशा	कृषि उपकरण	कटनी	कटनी स्टोन
खरगोन	मिर्च	सागर	कृषि उपकरण	पन्ना	आंवला
बुरहानपुर	केला	निवाड़ी	अदरक	सतना	टमाटर
खंडवा	प्याज	टीकमगढ़	अदरक	रीवा	बांस
देवास	बांस	छतरपुर	लकड़ी का फर्नीचर	सीधी	कारपेट
शाजापुर	प्याज			सिंगरौली	कोदो कुटकी
राजगढ़	संतरा	दमोह	चना	शहडोल	हल्दी
सीहोर	लकड़ी के खिलौने	नरसिंहपुर	तुअर दाल	उमरिया	महुआ
हरदा	बांस	छिंदवाड़ा	संतरा	अनूपपुर	कोदो कुटकी

वर्ष 2021 से 2022-23 तक की करोड़ों क्लेम राशि किसान को नहीं मिली

एक साल बाद भी नहीं मिल पाई खरीफ और रबी सीजन की फसल बीमा राशि

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

जिले में जिला सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंकों के माध्यम से किसनों ने खरीफ और रबी सीजन फ सल का बीमा कराया था। बीमा कंपनी ने किसानों से एक हेक्टेयर की10 फीसदी प्रीमियम राशि जमा कराई थी लेकिन बीमा कंपनी द्वारा वर्ष 2021 से 2022-23 तक की करोड़ों रुपए क्लेम राशि किसान को नहीं मिल पाई है। जिसके के कारण 9359 किसान आज भी बीमा कंपनी और कृषि विभाग के चक्कर काट रहे है। वहीं एक जुलाई से नया सीजन शुरू होने वाला है और खरीफ फसलों का बीमा शुरू कराया जाएगा। रबी और खरीफ सीजन की फसलें प्राकृतिक आपदाओं से खराब हो गई थी। जिनका 30 से 40 फीसदी नुकसान बताया गया था। किसान ने एक हेक्टेयर की 10 फीसदी प्रीमियम राशि फसल बीमा कंपनी के पास जमा कराई थी। जिसमें 2 फीसदी किसान, 4 फीसदी केंद्र सरकार और 4 फीसदी प्रदेश सरकार ने जमा की थी। वर्ष 2021 खरीफ फसल के 25753 किसानों में से 23250 किसानों की बीमा क्लेम राशि 81539154 रुपए आए थे। वर्ष 2021-22 की रबी सीजन फसल में 30902 में से 24076 किसानों को 94221326 रुपए क्लेम की राशि दी गई थी। अब वर्ष 2022, 2022-23 की खरीफ और रबी सीजन की फसलों का बीमा क्लेम नहीं मिल पाया है। जिसके लिए किसान बैंक, विभाग और बीमा कंपनी के चक्कर काट रहा रहा है।

यह हुई थी किसानों से प्रीमियम राशि जमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंकों के माध्यम से रबी और खरीफ सीजन की फसलों का बीमा कराया गया था। वर्ष 2021 की खरीफ फसल में 25753 किसानों ने फसल बीमा कराया था। जिसमें 1657194 रुपए की प्रीमियम राशि जमा की थी। सर्वे रिपोर्ट के बाद बीमा कंपनी ने 23250 किसानों को 81539154 रुपए का क्लेम दिया था। वहीं वर्ष 2021-22 की रबी फसल में 30902 किसानों ने फसल बीमा कराया था। जिसमें 1 करोड 67 लाख रुपए की प्रीमियम राशि जमा की थी। बीमा कंपनी ने 24076 किसानों को 94221326 रुपए का क्लेम दिया था।

30 से 40 फीसदी हुआ था नुकसान

बीमा कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि रबी और खरीफ सीजन में प्राकृतिक आपदा से 30 से 40 फीसदी नुकसान फसलों को हुआ था। जिसकी सर्वे रिपोर्ट संबंधित विभागों को सौंपी गई थी। वर्ष 2021-2021-22 का क्लेम किसानों को दे दिया गया है। उसमें 9359 किसान बीमा राशि के लिए भटक रहे है।

सर्वे रिपोर्ट शासन और कंपनी के पास पहुंच गई है। खरीफ और रबी सीजन की फसलों का क्लेम अभी नहीं आया है। शासन और कंपनी स्तर पर फसल बीमा देने की तैयारी की जा रही है। एक जुलाई से नया सीजन शुरू हो जाएगा। उसमें वर्ष 2023 के किसानों की फसलों का बीमा कराया जाएगा।

शिवाजी राजा परमार, जिला प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी टीकमगढ़

वर्ष 2022 और 2022-23 का नहीं मिला किसानों को क्लेम

जिले में वर्ष 2022 में खरीफ के 93741 किसानों ने सोयाबीन, उड़द, मूंगफली और तिल फसल का बीमा कराया था। जिसकी प्रीमियम राशि 1 करोड़ 26 लाख रुपए जमा इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा की है। वहीं 2022-23 में रबी के 101736 किसानों ने गेहूं, सरसों के साथ अन्य फसल का बीमा कराया था। जिसकी प्रीमियम राशि 1 करोड़ 29 लाख रुपए जमा कराई थी, दोनों सीजन खत्म होने के बाद भी प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसलों की क्लेम राशि किसानों को नहीं मिल पाई है।

5 हजार हेक्टेयर में होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें पेप्सिको

एक जिला-एक उत्पाद... अब शुगर फ्री आलू की ब्रांडिंग करेगा इंदौर

इंदौर। जागत गांव हमार

एक जिला-एक उत्पाद (वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट) में इंदौर का उत्पाद आलू है। इंदौर में जिस आलू का उत्पादन होता है, उसकी खास बात यह है कि यह शुगर फ्री होता है, जिसकी विदेशों में काफी मांग है। अब जिला प्रशासन इसी शुगर फ्री आलू की ब्रांडिंग करेगा, इसके लिए जल्द ही एक कॉन्फ्रेंस भी इंदौर में होगी। अभी इंदौर में 45 हजार हेक्टेयर में आलू की खेती होती है। यह एक साल पहले तक 40 हजार हेक्टेयर थी। 5 हजार हेक्टेयर का रकबा इसका बढ़ा है। कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी ने बताया कि आलू की खेती बढ़ी है। अब हमारा उद्देश्य इसकी प्रोसेसिंग को और उन्नत करना है। साथ ही शुगर फ्री आलू की ब्रांडिंग का काम भी हम करने जा रहे हैं। अभी हमारे यहां 45 में से 5 हजार हेक्टेयर में किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पेप्सिको, आईटीसी सहित अन्य कंपनियां शामिल हैं, जो यहां के किसानों से कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करवा रही हैं। ऐसे किसानों की संख्या 500 से ज्यादा है। कलेक्टर ने माना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को अच्छी क्वालिटी का बीज और खाद मिल जाता है, इससे फसल का उत्पादन भी अधिक होता है। कंपनियों को भी इससे फायदा है। हमारा फोकस प्रोसेसिंग को बढ़ाना है।

युवाओं को फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ेंगे

कलेक्टर ने कहा कि पोटेटो पाउडर बनाने पर भी काम हुआ था, लेकिन वह अभी इतना सफल नहीं हुआ है। हमने कृषि विभाग को निर्देश दिए गए कि युवाओं को फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। इस योजना की जानकारी देने के लिए शीघ्र ही कार्यशाला आयोजित की जाए। इस योजना के तहत छोटे और लघु खाद्य व्यवसाय और राजस्व को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी और अन्य आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।

आलू के अलावा सब्जियों का प्रोडक्शन एरिया भी बढ़ा

कृषि विभाग के मुताबिक इंदौर में आलू के बाद सब्जियों का प्रोडक्शन एरिया बढ़ा है। सिर्फ गाजर का रकबा अब जिले में 10 हजार हेक्टेयर का हो चुका है। इसके अलावा अन्य सब्जियां भी ज्यादा उगाई जाने लगी है।

डेढ़ दशक में जन-सहयोग से विकसित राज्य के रूप में उभरा मप्र

मप्र की विकास रिपोर्ट-2022 के अनुसार राज्य में आए बदलाव से मप्र बीमारू से विकसित प्रदेशों की पंक्ति में उदाहरण बन कर खड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने मप्र को अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय बना दिया है। सड़क, बिजली, पानी, कृषि, पर्यटन, जल-संवर्धन, सिंचाई, निवेश, स्व-रोजगार और अधो-संरचना विकास के साथ उन सभी पहलुओं पर सर्वांगीण विकास की नवीन गाथा लिखी गई।

बेहतर वित्तीय प्रबंधन और चौतरफा विकास से आज प्रदेश की विकास दर 19.7 प्रतिशत है, जो देश में सर्वाधिक है। देश की अर्थ-व्यवस्था में मध्यप्रदेश 4.6 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में बीते दशक में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर निरंतर बढ़ रही है। वर्ष 2001-02 में 4.43 प्रतिशत की दर आज बढ़ कर 16.43 प्रतिशत हो गई है प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 71 हजार 594 करोड़ रूपये से बढ़ कर 13 लाख 22 हजार 821 रूपये हो गया है। वर्ष 2001-02 में प्रति व्यक्ति आय 11 हजार 718 रूपये थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़ कर एक लाख 40 हजार 583 रूपये हो गई है। राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर विगत एक दशक में राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर से अधिक रही है।

विकास प्रक्रिया में अधो-संरचना के महत्व के मद्देनजर मध्यप्रदेश में निरंतर अधो-संरचना विकास हो रहा है। अधो-संरचना बजट जो वर्ष 2002-03 में 3873 करोड़ रूपए था, वह वर्ष 2023-24 में बढ़ कर 56 हजार 256 करोड़ रुपए हो गया है। एक समय था जब बिजली आती कम थी और जाती ज्यादा थी। आज प्रदेश बिजली क्षेत्र में आत्म-निर्भर है और 24 घंटे बिजली की उपलब्धता है। वर्ष 2003 में ऊर्जा क्षमता 5173 मेगावाट थी, जो बढ़ कर 28 हजार मेगावाट हो गई है।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश अग्रणी है। ओंकारेश्वर में लगभग 3500 करोड़ के निवेश से 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर सोलर पॉवर प्लांट का कार्य प्रारंभ हो गया है। किसानों के खेतों में 50 हजार सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य है। विश्वधरोहर साँची बहुत जल्द सोलर सिटी के रूप में विकसित होकर देश में अपनी अलग पहचान बनायेगा।

अच्छी सड़कें विकास की धुरी होती है। एक समय था, तब यह पता ही नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। अब गाँव-गाँव, शहर-शहर अच्छी गुणवत्तायुक्त सड़कों का जाल बिछाया गया हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2001-02 में 44 हजार किलोमीटर सड़कें थी, अब 4 लाख 10 हजार किलोमीटर सड़कें बन गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई के 40 हजार करोड़ की लागत के 35 कार्य स्वीकृत हैं। अटल, नर्मदा और विंध्य प्रगति पथ के साथ मालवा, बुंदेलखंड और मध्य विकास पथ निर्मित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सभी रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करने के लिए 105 रेलवे ओवर ब्रिज के साथ 334 पुलों का निर्माण हो रहा है। साथ ही 86 हजार करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं के कार्य चल रहे हैं। वर्ष 2009 से

2014 के बीच जहाँ प्रदेश को औसतन 632 करोड़ रूपए का रेलवे बजट मिलता था, वहीं वर्ष 2022-23 में 13 हजार 607 करोड़ का रेलवे बजट प्रावधान मिला है, जो इक्कीस गुना अधिक है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में प्रदेश के 80 रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे। अत्याधुनिक रानी कमलापति स्टेशन देश में एक मॉडल बना है। एक वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ हो चुकी है और आज प्रधानमंत्री श्री मोदी मध्यप्रदेश को 2 और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने वाले हैं। प्रदेश में हवाई सेवाओं का विस्तार भी निरंतर हो रहा है।

प्रदेश में कृषि को लाभ का धंधा बनाना के लिए सिंचाई क्षमताओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। वर्ष 2003 में सिंचाई क्षमता केवल 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2022 में बढ़ कर 45 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। वर्ष 2025 तक सिंचाई क्षमता को बढ़ा कर 65 लाख हेक्टेयर किये जाने पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। हर घर जल से नल योजना पर तेज गति से कार्य हो रहा है, अभी तक लगभग 50ल घरों तक नल से जल पहुँच चुका है। आजादी के अमृत काल में प्रदेश में अब तक 5936 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण किया जा चुका है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण में बांध, लिंक नहर तथा पॉवर हाउस का निर्माण कार्य इस वर्ष प्रारंभ होगा। अटल भू-जल योजना में भी लगभग 700 ग्राम पंचायतों में वॉटर सिक्युरिटी प्लान बनाए गए हैं। अधो-संरचना विकास और बेहतर वित्त प्रबंधन के साथ कृषि प्रधान होने की वजह से प्रदेश में तेज गति से कृषि विकास और किसान-कल्याण के कार्य भी किए जा रहे हैं। लगातार 7 बार प्रतिष्ठित कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश ने गेहूँ उपार्जन में पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश का सोने जैसे दानों वाला गेहूँ अमेरिका सहित अनेक देशों में निर्यात होता है। अब इसके निर्यात के लिए प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाई गई है। कृषि विकास दर जो वर्ष 2002-03 में 03 प्रतिशत थी, वह वर्ष 2020-21 में बढ़ कर 18.89 प्रतिशत हो गई है। खेती और एलाइड सेक्टर का बजट भी 600 करोड़ से बढ़ कर 53 हजार 964 करोड़ हो गया। खाद्य उत्पादन भी इस अवधि में 159 लाख मीट्रिक टन से बढ़ कर 619 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

उद्यानिकी फसलों का रकबा 4 लाख 67 हजार हेक्टेयर से बढ़ कर 25 लाख हेक्टेयर हो गया है। फसल उत्पादन 224 लाख मीट्रिक टन से बढ़ कर 725 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। फसल उत्पादकता 1195 किलोग्राम से बढ़ कर 2421 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। किसान-कल्याण के ध्येय से प्रदेश में गत 3 वर्षों में फसलों की नुकसानी पर 4000 करोड़ से अधिक की राहत राशि वितरित की गई है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक डिफाल्टर किसानों का 2123 करोड़ का ब्याज माफ करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना प्रारंभ की गई है।

टमाटर के भाव असमान पर, किसानों को नहीं कोई फायदा

टमाटर की कीमतों ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। उपभोक्ता मामले विभाग के प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन के मुताबिक 27 जून, 2023 को टमाटर की अधिकतम खुदरा कीमतें 122 रुपए किलो तक पहुंच गईं, जबकि किसान प्राइवेट ट्रेडर्स को घाटे में टमाटर बेचने को मजबूर हैं। इस सीजन में भी टमाटर किसान लागत न निकाल पाने वाली दर पर अधिकतम 10 रुपए थोकभाव में प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचने को मजबूर हुए हैं। किसानों की आय दोगुना करने की सिफारिश वाली दलवई कमेटी की रिपोर्ट में आलू, प्याज के साथ टमाटर की बेहतर खरीद-बिक्री करने और किसानों की सुविधाओं के लिए कई सिफारिशें भी की गई थीं।

आंध्र प्रदेश में चित्तूर जिल में स्थित चौडेपल्ले में फॉर्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले किसान मोहन रेड्डी बताते हैं कि जनवरी से फरवरी तक सीजन में 3 रुपए किलो तक टमाटर बेचा है, गर्मी में टमाटर के दामों में बढोत्तरी हुई लेकिन अधिकतम 8 से 10 रुपए में ही उनके टमाटर प्राइवेट ट्रेडर्स ने खरीदे। मोहन रेड्डी बताते हैं कि प्रति एकड़ टमाटर उगाने की लागत 2 से 3 लाख रुपए आती है, यदि किलो में बात करें तो प्रति किलो टमाटर उगाने की लागत 8 से 10 रुपए की है। हम लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। मोहन रेड्डी यह भी बताते हैं कि कर्ल लीफ वायरस हर साल प्रभावी हो रहा है और टमाटर की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस साल भी टमाटर की फसल को इस वायरस से नुकसान हुआ है। टमाटर ट्रेडर्स को बॉक्स में बेचे जाते हैं एक बॉक्स में करीब 15 किलो टमाटर होते हैं। इन दिनों बढ़ी हुई कीमतों के पीछे सीजनल अवधारणा बताई जा रही है। फेडरेशन ऑफ फार्मर्स एसोसिएशंस के प्रेसीडेंट पी चेंगल रेड्डी ने बताया कि कुछ महीनों में वर्षा के कारण दक्षिण भारत में टमाटर की अत्यधिक फसल नष्ट हुई है, जिसके कारण उत्पादन कम हुआ है। किसान मार्केट यार्ड में अधिकतम 10 रुपए प्रति किलो की दर से ही टमाटर हासिल कर सके हैं। फसल नष्ट होने के कारण बीते हफ्ते ही टमाटर की खुदरा कीमतें बढ़ी हैं जो अगले दस से पंद्रह दिनों में सामान्य हो जाएंगी।

उपभोक्ता मामले विभाग में प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन की ज्वाइंट डायरेक्टर लालरामदिनपुई रेन्थलेई ने कहा यह एक सीजनल चीज है। हर साल जब तक नई आवक नहीं आ जाती है तब तक इस सीजन में टमाटर की कीमतें बढ़ जाती हैं। अनियमित वर्षा के कारण टमाटर की फसल भी खराब हुई है, हालांकि नई फसल के आते ही कीमतें सामान्य हो जाएंगी। उपभोक्ता मामले विभाग के मुताबिक जून, 2023 के महीने में ही टमाटर की कीमतों में देशभर में वैरिएबिलिटी न्यूनतम कीमत 10 रुपए से लेकर अधिकतम कीमत 122 रुपए तक रही है। पी. चेंगल रेड्डी के मुताबिक कीमतों के इन उतार-चढ़ाव के जिम्मेदार प्राइवेट ट्रेडर्स हैं।

दलवई कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों द्वारा 58 फीसदी टमाटर प्राइवेट ट्रेडर्स को बेचा जाता है। प्रोसेसर्स किसानों से टमाटर नहीं खरीदते हैं। न ही सहकारी संस्थाएं और सरकार की एजेंसियां इस खरीद में रुचि दिखाती हैं। इसलिए टमाटर की फसल को मजबूरन किसान को प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना पड़ता है। दलवई कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मास कंजप्शन वाले टमाटर को संवेदनशील उत्पाद बताते हुए इसकी आय और क्षति को लेकर विशेष ध्यान देने की बात कही गई थी। इसी रिपोर्ट में टमाटर के लिए सप्लाई चेन को मजबूत बनाने की बात कही गई थी। इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन भी चलाया गया जिसमें खेत से सीधा उपभोक्ता तक चीजें पहुंचाने की योजना बनी लेकिन इसका असर नहीं दिखाई दिया। दलवई कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशों के मुताबिक कोल्ड चैन, मॉडर्न पैक हाउसेज और पूलिंग प्वाइंट्स के साथ गांव से ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाओं जैसे मुद्दों पर भी खासा ध्यान नहीं दिया गया है। न ही कोई ऐसी बॉडी बनाई गई है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के व संस्थाओं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सदस्य शामिल हों और वे हर सीजन में टमाटर जैसी फसलों को लेकर एडवांस गाइडेंस करें। उत्पादन वर्ष 2021-22 में 20.69 मिलियन टन टमाटर हुआ था जबकि 2022-23 में 20.62 मिलियन टन ही टमाटर होने का अनुमान है। टमाटर की कीमतें अगले पंद्रह से बीस दिनों में कम हो सकती हैं लेकिन किसान लागत निकालने में असफल साबित हो रहे हैं।

खेती के लिए वरदान है जैव अभियांत्रिकी

जैव अभियांत्रिकी एक अभियांत्रिकी शाखा है जो जैविक पदार्थों, जैव विज्ञान और इंजीनियरिंग के संयोग से जुड़ी होती है। यह विज्ञान और इंजीनियरिंग के माध्यम से जीवविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करके, जैविक पदार्थों और विषयों के विकास, उत्पादन, प्रसंस्करण और उपयोग के लिए तकनीकी समाधान ढूंढती है। जैव अभियांत्रिकी का उद्देश्य जैविक पदार्थों की प्रक्रियाओं को समझना, उन्हें सुधारना और उन्हें उपयोगी उत्पादों में रूपांतरित करना होता है। यह उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादकता और स्थायित्व में सुधार करने का एक मार्ग प्रदान करती है। जैव अभियांत्रिकी के तत्वों के उपयोग से खाद्य उत्पादों, औषधीय उत्पादों, जैविक ईंधन, स्वच्छता तकनीक, पर्यावरणीय तकनीक, और बायोमेडिकल उत्पादों का विकास किया जाता है।

जैव अभियांत्रिकी में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि जैव प्रोसेस इंजीनियरिंग, जैविक इंस्ट्रूमेंटेशन, जैव संपादन, जैविक पदार्थ निर्माण आदि। इन्ही के द्वारा आज जैव अभियांत्रिकी खेती में विभिन्न तरीकों से उपयोगी होती है। इसके द्वारा खेती क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों और जैविक पदार्थों का उपयोग करके फसलों की प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुधारा जा सकता है। यह खेती के निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोगी होती है...

जैव अभियांत्रिकी खेती में सबसे पहले जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, जैविक उर्वरक, जैविक बीज, और प्राकृतिक प्रबंधन प्रणाली आदि को शामिल किया जा सकता है। जैविक खेती में जैविक पदार्थों का उपयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, पौधों का प्रभावशाली प्रबंधन होता है, कीट-रोगों का प्रबंधन संभव होता है, और प्रदायित्व में सुधार होता है।

जैव अभियांत्रिकी खेती में जैव उर्वरकों का उपयोग करने से फसलों को पोषण मिलता है और उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ये उर्वरक प्राकृतिक जैविक पदार्थों से बने होते हैं, जो पौधों को विभिन्न पोषक तत्व और मिनरल्स प्रदान करते हैं। जैव उर्वरक प्रदूषण में कमी लाते हैं और मिट्टी की उपजाऊता को बढ़ाते हैं।

जैविक अभियांत्रिकी खेती में जैविक कीटनाशकों का उपयोग करने से कीट और पशुओं के प्रभावी नियंत्रण का एक भी समाधान होता है। इन कीटनाशकों में पौधों द्वारा उत्पन्न जैविक पदार्थों, मिट्टी से प्राप्त कीटनाशकों और माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का उपयोग किया जाता है। ये कीटनाशक पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित होते हैं। जैव अभियांत्रिकी खेती में जैविक बीजों का उपयोग करने से उत्पादकता बढ़ती है और प्रतिरोधशीलता में सुधार होता है। जैविक बीज उच्च गुणवत्ता और विषमुक्त होते हैं, जो फसलों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में मदद करते हैं।

यही कारण है कि आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व भी कृषि क्षेत्र में तकनीक के विकास को लेकर लगातार सक्रीय भागीदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। जैव अभियांत्रिकी कृषि में सुधारों को लेकर एक बड़ी पहल है जिसकी सहायता से हम कृषि में उन्नत और उच्च उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं।

जिले में कुल 70 एवं 80 जगहों पर सारस गणना कार्य को अंजाम दिया गया

सारस गणना-2023 में बालाघाट जिला अव्वल दूसरे स्थान पर गोंदिया जिला

रफी अहमद अंसारी, बालाघाट।

जिला पुरातत्व एवं संस्कृति परिषद बालाघाट के नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि बालाघाट कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा एवं सीईओ जिला पंचायत डीएस रणदा के मार्गदर्शन एवं सहयोग से सेवा संस्था वन विभाग के साथ सारस गणना का कार्य किया जा रहा है सारस गणना में पूर्व वर्षों की तरह बालाघाट जिला अग्रणी रहा है यहां तीन जिलों की अपेक्षा बालाघाट में सर्वाधिक 49 सारस पाए गए हैं। दूसरे स्थान पर गोंदिया जिला है, जहां 31 सारस तथा भण्डारा जिले में महज 4 सारस की गणना की गई है। जहां जिला प्रशासन द्वारा सेवा संस्था के सारस संरक्षण कार्य की सराहना की गई एवं आगे भी सारस संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करते रहने की बात कही। दरअसल, पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण तथा संवर्धन के लिए कार्यरत सेवा संस्था अध्यक्ष सावन बहेकार के नेतृत्व में तथा बालाघाट उत्तर-दक्षिण वनमंडल एवं जिला पुरातत्व एवं संस्कृति परिषद बालाघाट के सहयोग से सारस गणना का कार्य पारंपारिक तथा शास्त्रीय पध्दती से किया गया। गोंदिया में छह दिनों तक चली सारस गणना।

कुल 70 एवं 80 जगहों पर सारस गणना- बालाघाट जिले में कुल 70 एवं 80 जगहों पर सारस गणना कार्य को अंजाम दिया गया। बालाघाट जिले के लिए 25 तथा गोंदिया भंडारा जिले में 39 टीमे बनाकर सारस के रहवास स्थल पर सुबह 5 बजे से 9 बजे तक विभिन्न स्थानों पर प्रत्यक्ष जाकर गणना की गई।

कैसे की गई गणना

प्रत्येक टीम में 2-4 सेवा संस्था के सदस्य तथा डीएटीसीसी सदस्य वन विभाग कर्मचारियों का समावेश किया गया था। संस्था के सदस्यों द्वारा पुरे वर्षभर सारस के विश्राम स्थल, प्रजनन अधिवास तथा भोजन के लिए प्रयुक्त भ्रमण पद पर नजर रखी जाती है साथ ही सारस के अधिवास एवं उनके आसपास रहनेवाले किसानों को सारस का महत्व बताकर उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रेरित किया जाता है। परिसर के स्कूल तथा महाविद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को पर्यावरण एवं सारस संवधज्न एवं संरक्षण से संबंधित कायज्क्रमों के माध्यम से सारस संरक्षण अभियान से जोड़ा जाता है ज्ञात हो कि पूवज् में सारस संरक्षण करने वाले किसान आमजन को सारस मित्र सम्मेलन के माध्यम से सेवा संस्था द्वारा कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में सारस मित्र सम्मेलन आयोजित कर किसानों सारस मित्रो को कलेक्टर बालाघाट के हस्ते सम्मानित किया गया था।

सीमाओं का बंधन नहीं

विदत हो कि बाघनदी एवं वैनगंगा नदी महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश के बालाघाट तथा गोंदिया जिलों को विभाजित करती है भौगोलिक दृष्टिकोण से नदी के दोनों ओर के प्रदेश की जैवविविधता मे काफी समानता पायी जी है। अतः कुछ सारस के जोडें अधिवास तथा भोजन के लिए दोनों ओर के प्रदेशों में समान रूप से विचरण करते पाए जाते हैं। सीमाओं का बंधन उनके लिए मायने नही रखता जो मनुष्य के लिए एक अच्छा सबक है आकड़ों की विश्वसनियता एवं सारस की उपस्थिती पर संदेह की गुंजाईश ना रहे इसके लिए दिनांक 19 से 23 तक प्रतिदिन सुबह एवं शाम सभी सारस अधिवास पर जाकर सारस की स्थिती का जायजा लिया गया। जिसमे खेत, तालाब, नदियों पर जाकर स्थानिय लोगों से भी बातचित की गयी। दिनांक 17 जून को बालाघाट जिले में 25 टीमो द्वारा 60 से 70 स्थानों पर प्रकल्प प्रभारी श्री अविजित परिहार के मागज्दशज्न में गणना कार्य किया गया गोंदिया जिले में दिनांक 18 जून को कुल 39 टीमों में कुल 70 से 80 स्थानों पर जाकर जिसमें हर स्थान पर वनविभाग के कर्मचारियों के साथ गणना की गयी थी

कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक

नर्मदापुरम। कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर जिला नर्मदापुरम की पंचम वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक आज दिनांक 27.06.2023 को कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में आयोजित की गयी जिसकी अध्यक्षता निदेशक, भाकृअनुप.- कृषि तकनिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान,जबलपुर डॉ. एसआर के सिंह ने की। बैठक में संचालक विस्तार सेवाएं जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय से प्रतिनिधि डॉ संजय वैशम्पायन, उपसंचालक कृषि जेआर हेडाऊ, उपसंचालक उद्यानकी रीता उइके, जिला विकास प्रबंधक (नाबार्ड) जिला नर्मदापुरम दीपक पाटिल एवं वन विभाग के प्रतिनिधि डिप्टी रेंजर बनखेडी विष्णु पुजारी, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी पवन सिंह पवार, कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, भाऊसाहब भुस्कुटे स्मृति लोक न्यास गोविंदनगर के सहसचिव केशव माहेश्वरी, सदस्य भूपेन्द्र सिंह पटेल, अनिल बरोलिया, मनोज राय एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों एवं जिले के प्रगतिशील कृषकों की उपस्थिति में संपन्न की गई। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया गया, तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों को श्रीफल एवं मोमंटो प्रदान कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया । अंत मे निदेशक डॉ. एसआरके सिंह जी द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करते हुए किसान बंधुओ को सबसे बढ़ा कृषि वैज्ञानिक कहा साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा किसानों के हित मे किये जा रहे कार्यों को सबके समक्ष रखा गया, उन्होंने आगे बताते हुए कहा की अगले वर्ष कृषि विज्ञान केंद्र अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मनाने जा रहा है। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य धन होता है इसलिए खेत मे स्वयं के खाने के लिए प्राकृतिक फसल, सब्जी उगाएं।

डॉ संजीव कुमार गर्ग द्वारा किया गया

बैठक में प्रगतिशील कृषक गोपाल कुशवाहा, बलकिशन कुशवाहा, शरद वर्मा, दिनेश चौधरी, अंकित पटेल, सुभाष पटेल एवं जिले के अन्य प्रगतिशील किसान, कृषि विज्ञान केंद्र गोविन्दनगर से वैज्ञानिक ब्रजेश कुमार नामदेव, डॉ. देवीदास पटेल, डॉ. आकांक्षा पांडे, लवेश चौरसिया, राजेन्द्र पटैल, डॉ. प्रवीण सोलंकी, पंकज शर्मा, विकास मोहरीर, राहुल माझी एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत मे आभार प्रदर्शन कृषि विज्ञान केंद्र गोविन्दनगर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. संजीव कुमार गर्ग द्वारा किया गया।

फसल अच्छी होने की कामना की

पहले धरती मां का पूजन और फिर किसानों ने की बोवनी की शुरुआत

उज्जैन। जागत गांव हमार

फसलों की बुवाई के पहले धरती को अपनी मां मानने वाले किसानों ने सबसे पहले धरती माता की पूजा अर्चना कर उन्हें पूजन सामग्री अर्पित कर यह फसल अच्छी हो जाए, इसकी कामना की। सारोला क्षेत्र के किसान अशोक प्रजापत ने बताया कि बारिश शुरू होते ही खेतों बोवनी का कार्य शुरू कर दिया गया है। किसान ने बताया कि किसानों ने बोवनी के पहले अच्छी फसल के लिए खेतों को भू-देवी मानकर पूजन पाठ कर बोवनी की शुरुआत करते हुए खेत की धरती पर लाल कपड़े में श्रृंगार और चढ़ावा रखकर भगवान से अच्छी फसल की कामना की है। वहीं, ग्राम रातड़िया के किसान प्रेम चौधरी ने बताया कि किसानों द्वारा अच्छी फसल के लिए खेतों को भू-देवी मानकर पूजन किया जाता है और कृषि यंत्रों की भी पूजा की जाती है। इसके बाद ही बोवनी शुरू होती है। वर्षा ऋतु में सोयाबीन, मक्का, मूंग और ज्वार की फसल मालवा क्षेत्र में बोई जाती है।

वर्धमान फैब्रिक्स इंडस्ट्री में 19 मेगावाट बिजली बनाई

गौ-काष्ठ से पहली बार कैप्टिव पावर प्लांट मे बिजली का किया उत्पादन

भोपाल। भारत ही नहीं, वल्कि पूरे विश्व मे पहली बार वर्धमान फैब्रिक्स इंडस्ट्री (बुधनी,मध्य प्रदेश) के 24 मेगावाट के पावर प्लांट को गौ-काष्ठ से चलाकर बिजली का उत्पादन किया। खुशी की बात यह है कि गौ-काष्ठ कोल की तरह रिएक्ट कर रही थी और यह गौ-काष्ठ का ट्रायल रन सक्सेसफुल रहा, इस प्रक्रिया में कोल का रिडक्शन किया गया और रिडक्शन किए गए कोल की जगह गौ-काष्ठ का उपयोग किया गया। गौ-काष्ठ के उपयोग से पावर प्लांट मे बिजली बनाने से बहुत बड़ी तादाद मे कोल को बचाया गया। एक साल की कड़ी मेहनत के बाद गौ-काष्ठ से पावर प्लांट को चलाने में सफलता हासिल हुई।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी) की टीम की देखरेख में बुदनी की वर्धमान इंडस्ट्रीज में कैप्टिव पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के साथ फैब्रिक के निर्माण में ईंधन के रूप में गो काष्ठ का उपयोग हुआ। इससे 19 मेगावाट बिजली बनाई गई। कंपनी के इंजीनियरों और सीपीसीबी के वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रयोग सफल साबित हुआ है। गौ-काष्ठ बिल्कुल कोयले जैसी ही जली। सीपीसीबी के वैज्ञानिक डॉ. योगेंद्र कुमार सक्सेना ने बताया कि गो काष्ठ के उपयोग से 30 प्रतिशत प्रदूषण कम होता है। 5 साल पहले भोपाल में गो काष्ठ से अंतिम संस्कार की शुरुआत हुई थी। वर्धमान फैब्रिक्स के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अरविंद कुमार राय ने बताया कि सीपीसीबी ने कैप्टिव पॉवर प्लांट में गो काष्ठ के उपयोग के लिए हमसे संपर्क किया। हमारे यहां 135 टन प्रतिघंटे क्षमता का बॉयलर है, जिसमें हम अधिकतम 115 टन प्रति घंटे भाप का उत्पादन करते हैं।

लांट में अधिकतम 19 मेगावाट बिजली उत्पादन

यह भाप पहले कैप्टिव पावर प्लांट की टरबाइन को रोटेट करती है और 24 मेगावाट के प्लांट में अधिकतम 19 मेगावाट बिजली बनती है। इसके बाद यही भाप फैब्रिक के उत्पादन में उपयोग होती है। इसके लिए रोजाना 360 टन कोयला इस्तेमाल होता है। सीपीसीबी के निर्देशन में हुए ट्रायल में 36 टन गो काष्ठ का उपयोग किया गया। इससे भाप, उसके बाद बिजली और फैब्रिक के उत्पादन में कोई अंतर नहीं देखा गया। धीरे-धीरे करके 100 प्रतिशत तक गो काष्ठ का उपयोग किया जा सकता है। सीपीसीबी के वैज्ञानिक डॉ. योगेंद्र कुमार सक्सेना के साथ रामेश्वर बंदेवार, सुनील कोल्हटकर और सचिन साहू ने पॉल्यूशन से इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की। सीपीसीबी के रीजनल डायरेक्टर पी. जगन ने कहा कि हमने ट्रायल रन कराया है और यह सफल रहा है। मॉनिटरिंग के रिजल्ट आने में कुछ दिन का समय लगता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मनरेगा से सहेजी जा रही बारिश की बूंदें

बारिश के बहते जल को भूमि में उढेलने के लिए बनी 1038 जल संरचनाएं

37 लाख 49 हजार 415 घन मीटर जल स्टोर होगा इस वर्ष की जलसंरचनाओं से

खरगोन। जागत गांव हमार

वास्तव में जल ही जीवन है। जल के उपयोग और उपभोग से ही पृथ्वी पर होने वाली हर एक क्रिया सम्पादित होती है। चाहे बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में बनने वाला लोहा हो या फार्मेसी की कंपनी में बनने वाली कोई दवाई हर किसी वस्तु में पानी का उपयोग होता है। आसमान से बरसने वाली इन्ही जल की बूंदों को सहेजने के लिए गत दिसम्बर से जून माह तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मनरेगा ने जल जलसंरचनाएं बनाई है। जिनसें सीधे जल को भूमि में उढेलने के साथ-साथ सिंचाई व वन्य जीवों के अतिरिक्त पशुओं के उपयोग में उपयोगी होंगे। मनरेगा पीओ श्याम रघुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि बारिश समाप्त होते ही दिसम्बर से जल संरक्षण के कार्य प्रारम्भ हुए हैं। इसमें 18 हजार से 20 हजार घन मीटर जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर तथा निस्तार तालाब व तालाब (वॉटर पॉंड) से 3000-3000 हजार घन मीटर जल रोका जा सकता है। इसके अलावा खेत तालाब, चेक डेम व स्टॉप डेम से 800 से 1000 हजार घन मीटर जल सहेजने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा कंटूर ट्रेंच और सोख पीठ, रिचाजर् पीठ आदि भी संरचनाएं है जो जल संरक्षण के लिए उत्तम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पीओ आरके पाटीदार ने बताया कि वॉटर शेड के तहत भी जिले में 13 अमृत सरोवर और 41 अन्य जल संरक्षण के कार्य किये गए हैं। इसमें चेकडैम, खेत तालाब, परकोलेशन टैंक, कंटूर ट्रेंच शामिल है।

वॉटर शेड से 6 लाख घन मीटर से अधिक जल संरक्षण होगा

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पीओ पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष वॉटर शेड से 13 अमृत सरोवर तालाब बनाये गए हैं। इनसे 3 लाख 58 हजार 215 घन मीटर जल स्टोर होगा। जबकि अन्य जल संग्रहण संरचनाओं के 41 कार्य पूर्ण हुए हैं। जिनसे 252400 घन मीटर जल एकत्रित होगा और भूमि के अंदर भी स्टोर होने की उम्मीद है। इस तरह वॉटर शेड के द्वारा 54 कायोर्ं से 6 लाख 10 हजार 615 घन मीटर जल सहेजा जाएगा।

मनरेगा से 31 लाख घन मीटर से अधिक जल रुकेगा

मनरेगा पीओ रघुवंशी ने बताया कि गत वर्ष समाप्ति के बाद अब तक 70 अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ है। इतना ही नहीं 277 खेत तालाब, 106 चेक डैम, 322 वॉटर पॉंड, 171 निस्तार तालाब, 38 स्टॉप डैम तथा 11 हेक्टेयर में कंटूर ट्रेंच बनाने का कार्य हुआ है। इन 984 सभी जल संरचनाओं से 31 लाख 38 हजार 800 घन मीटर जल संरक्षण एक आंकलन के अनुसार होगा।

प्राकृतिक जल प्रबंधन की दिशा में बेहतर कार्य हुआ

जिला पंचायत सीईओज्योति शर्मा ने बताया कि मनरेगा अंतर्गत जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण जिसे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कहा जाता है। इसमें 65 परसेंट न्यूनतम व्यय का प्रावधान होने के बावजूद जिला में लगभग 78 प्रतिशत का व्यय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में किया जा रहा है।

केवीके में कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किसानों को दिया गया उड़द का बीज

छतरपुर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव जिला छतरपुर में जलवायु समुत्थानशील कृषि पर नवाचार (निकरा परियोजना)के अन्तर्गत सिंगरावनकला ग्राम के कृषकों का कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें डॉ. कमलेश अहिरवार (वैज्ञानिक उद्यानिकी) के द्वारा उद्यानिकी फसलों में सामयिक सलाहके साथ उड़द फसल की खेती की वैज्ञानिक विधि पर विस्तार से परिचर्चा की गई तथा अतर सिंह (एग्रोमेट ऑब्जर्वर) द्वारा वर्तमान तथा आगामी आने वाले समय में मौसम मैं क्या परिवर्तन हो सकता है इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया साथ ही सभी कृषकों को उड़द फसल की किस्म शेखर -2 को प्रदर्शन के रूप में वितरण भी किया गया।

डॉ. आरके सिंह बेस्ट केवीके साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित

खरगोन। कृषि विज्ञान केन्द्र खरगोन में पदस्थ वैज्ञानिक डॉ. आरके सिंह ने इंडियन सोसायटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु में 22 से 24 जून को आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में क्लस्टर फ्रंटलाइन डेमोंस्ट्रेशन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एप्रोच फॉर डिसिमिनेशन ऑफ सुस्टेनेबल सोयाबीन टेक्नोलॉजी' प्रस्तुत किया था। डॉ. सिंह द्वारा खरगोन जिले के किसानों के मध्य उन्नत कृषि तकनीकी हस्तांतरण करने एवं सूचना संचार तकनीकी के माध्यम से सामयिक कृषि तकनीकी सलाह प्रेषित करने के लिए राष्ट्रीय सेमिनार में कर्नाटक सरकार के कृषि मंत्री एन चालूवेरा स्वामी एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के उपमहानिदेशक (कृषि प्रसार) डॉ यूएस गौतम ने बेस्ट केवीके साइंटिस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। डॉ. सिंह को सम्मानित किये जाने पर कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ जीएस कुलमी, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र के सह निदेशक डॉ. व्हायके जैन एवं समस्त वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई और शुभकामनांए दी।

पशुपालन मंत्री ने दी सभी योजनाओं की जानकारी

पशुपालकों के लिए बड़े काम की डेयरी पशुधन से बढ़ेगी किसानों की आमदनी

नई दिल्ली। जागत गांव हमार

भारत के पास पशुधन और मुर्गी पालन के विशाल संसाधन है, जो ग्रामीण जनता की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ ही आय का प्रमुख जरिया है। पशुपालन के माध्यम से कृषि में विविधता ग्रामीण आय में वृद्धि के प्रमुख चालकों में से एक है। मोदी सरकार के नौ वर्ष पूर्ण होने पर केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रूपाला ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग प्रमुख पशुधन रोगों के पूर्ण नियंत्रण, उन्मूलन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम लागू कर रहा है। विभाग पशुधन क्षेत्र के माध्यम से विशेष रूप से किसानों की आय बढ़ाने में मदद करने के सामान्य उद्देश्य से अन्य मंत्रालयों और हितधारकों के साथ मिलकर तालमेल करने के प्रयास कर रहा है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन: राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं उपलब्ध कराना है। अब तक इसमें 5.71 करोड़ पशुओं को शामिल किया गया है, 7।10 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए जा चुके हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 3.74 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। **देश में आईवीएफ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा:** कार्यक्रम के तहत अब तक 19,248 जीवन क्षम भ्रूण पैदा किए गए, 8661 जीवन क्षम भ्रूण स्थानांतरित किए गए और 1343 बछड़ों का जन्म हुआ।

सेक्स सॉर्टेड सीमेन या लिंग वर्गीकृत वीर्य तैयार करना- देश में 90 प्रतिशत तक सटीकता के साथ केवल मादा बछिया के जन्म के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन या लिंग वर्गीकृत वीर्य तैयार करना शुरू किया गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत, सुनिश्चित गर्भावस्था पर किसानों के लिए 750 रुपये या सॉर्टेड सीमेन की लागत का 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है।

डीएनए आधारित जीनोमिक चयन- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने स्वदेशी नस्लों के विशिष्ट जानवरों के चयन के लिए इंडसचिप विकसित किया है और रेफरल आबादी तैयार करने के लिए चिप का उपयोग करके 25000 जानवरों का जीनोटाइप किया है। दुनिया में पहली बार, भैंसों के जीनोमिक चयन के लिए बफचिप विकसित किया गया है और अब तक, रेफरल आबादी बनाने के लिए 8000 भैंसों का जीनोम टाइप किया गया है।

डेयरी कार्यों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों का सहयोग करना

गंभीर प्रतिकूल बाजार स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण संकट से निपटने के लिए डेयरी कार्यों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को आसान कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करके सहायता करना। वर्ष 2020-21 से 30/04/2023 तक, एनडीडीबी ने देश भर में 60 दुग्ध संघों के लिए 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 37,008.89 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण राशि के विरुद्ध 513.62 करोड़ रुपये की रियायती ब्याज सहायता राशि की मंजूरी दे दी और 373.30 करोड़ रुपये (नियमित रियायती ब्याज दर के रूप में 201.45 करोड़ रुपये और अतिरिक्त ब्याज अनुदान राशि के रूप में 171.85 करोड़ रुपये) जारी किए गए हैं।

डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

किसानों को उपभोक्ता से जोड़ने वाले शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचे सहित गुणवत्तापूर्ण दूध के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना और उसे मजबूत करना। वर्ष 2014-15 से 2022-23 (20 जून 2023) तक 28 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में 3015.35 करोड़ रुपए (केंद्रीय हिस्सेदारी 2297.25 करोड़ रुपए) की कुल लागत के साथ 185 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। योजना के तहत 20 जून 2023 तक मंजूर नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुल 1769।29 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मंजूर परियोजनाओं के अंतर्गत 1314।42 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया है।

राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन

भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने एनडीडीबी के साथ एक डिजिटल मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (एनडीएलएम) शुरू किया है। इससे पशुओं की उर्वरता में सुधार करने, पशुओं और मनुष्यों दोनों को प्रभावित करने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने, गुणवत्तापूर्ण पशुधन और घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए पशुधन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

नस्ल वृद्धि फार्म

इस योजना के तहत नस्ल वृद्धि फार्म की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों को पूंजीगत लागत (भूमि लागत को छोड़कर) पर 50 प्रतिशत (प्रति फार्म 2 करोड़ रुपए तक) की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब तक डीएएचडी ने 76 आवेदन स्वीकृत किए हैं और एनडीडीबी को सब्सिडी के रूप में 14.22 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि

योजना का उद्देश्य दूध प्रसंस्करण, शीतलन और मूल्य वर्धित उत्पाद सुविधाओं आदि घटकों के लिए दूध प्रसंस्करण, शीतलन और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे का निर्माण/आधुनिकीकरण करना है। डीआईडीएफ के तहत 31/05/2023 तक 6776.86 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 37 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं और 4575.73 करोड़ रुपए के ऋण के मुकाबले 2353.20 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। रियायती ब्याज दर के रूप में नाबार्ड को 88.11 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

पशु की पहचान और पता लगाने की क्षमता

53.5करोड़ जानवरों (मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर) की पहचान और पंजीकरण 12 अंकों के यूआईडी नंबर के साथ पॉलीयुरेथेन टैग का उपयोग करके की जा रही है। **संतान परीक्षण और नस्ल चयन:** गिर, शैवाल देशी नस्ल के मवेशियों और मुर्रा, मेहसाणा देशी नस्ल की भैंसों के लिए संतान परीक्षण कार्यक्रम लागू किया गया है।

पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास निधि

व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कंपनियों द्वारा डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन बुनियादी ढांचे और पशु चारा संयंत्र, मवेशी/भैंस/भेड़/बकरी/सुअर के लिए नस्ल सुधार टेक्नोलॉजी और नस्ल वृद्धि फार्म स्थापित करने और तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त पोल्ट्री फार्म के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए। अब तक, बैंकों द्वारा 309 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 7867.65 करोड़ रुपए है और कुल परियोजना लागत में से 5137.09 करोड़ रुपये सावधि ऋण है। रियायती ब्याज सहायता के रूप में 58.55 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम

इस योजना का मुख्य उद्देश्य टीकाकरण द्वारा आर्थिक और जूनोटिक महत्व के पशु रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और रोकथाम है। अब तक इयर टैग किए गए पशुओं की कुल संख्या लगभग 25.04 करोड़ है। एफएमडी के दूसरे दौर में अब तक 24.18 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। एफएमडी टीकाकरण का तीसरा दौर चल रहा है और अब तक 4.66 करोड़ जानवरों को टीका लगाया जा चुका है। अब तक 2.19 करोड़ जानवरों को ब्रुसेला का टीका लगाया जा चुका है। 16 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 1960 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) को हरी झंडी दिखाई गई है। 10 राज्यों में 1181 एमवीयू कार्यरत हैं।

पशुधन जनगणना-एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना

एकीकृत नमूना सर्वेक्षण दूध, अंडा, मांस और ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों (एमएलपी) का अनुमान सामने लाना। विभाग के बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी (बीएएचएस) के वार्षिक प्रकाशन में अनुमान प्रकाशित किए जाते हैं। हाल ही में, 2021-22 की अवधि के लिए बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी (बीएएचएस)-2022 प्रकाशित किया गया है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

योजना में मुख्य रूप से रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास; प्रति पशु उर्वरता में वृद्धि और इस प्रकार मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत, पहली बार, केन्द्र सरकार व्यक्तियों, एसएचजी, जेएलजी, एफपीओ, सेक्शन 8 कंपनियों, एफसीओ को हैचरी और ब्रूडर मदर इकाइयों के साथ पोल्ट्री फार्म स्थापित करने, भेड़ और बकरी की नस्लों की वृद्धि, फार्म, सूअर पालन फार्म और चारा एवं चारा इकाइयों के लिए सीधे 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। अब तक, डीएएचडी ने 661 आवेदन स्वीकृत किए हैं और 236 लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में 50.96 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

पशुधन जनगणना

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में परिवारों के स्तर तक उम्र, लिंग-संरचना आदि के साथ प्रजाति-वार और नस्ल-वार, पशुधन की आबादी के बारे में जानकारी प्रदान करना है। हाल ही में, सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पशुपालन विभाग की भागीदारी के साथ वर्ष 2019 में 20वीं पशुधन जनगणना पूरी हो गई है। 20वीं पशुधन जनगणना-2019 नामक अखिल भारतीय रिपोर्ट में शामिल पशुधन की प्रजाति-वार और राज्य-वार आबादी प्रकाशित हो चुकी है। उपरोक्त के अलावा, विभाग ने पशुधन और कुक्कुट पर नस्ल-वार रिपोर्ट (20वीं पशुधन जनगणना के आधार पर) भी प्रकाशित की है। दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी):- अब तक, एएचडी किसानों के लिए 27.65 लाख से अधिक नए केसीसी स्वीकृत किए गए हैं।

भारत में पशुओं की संख्या

पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। यह 2014-15 से 2020-21 के दौरान (स्थिर कीमतों पर) 7.93 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ा है। कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुधन का योगदान सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) (स्थिर कीमतों पर) 24.38 प्रतिशत (2014-15) से बढ़कर 30.87 प्रतिशत (2020-21) हो गया है। पशुधन क्षेत्र का योगदान 2020-21 में कुल जीवीए का 6।2 प्रतिशत है। 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन गोजातीय (मवेशी, भैंस, मिथुन और याक), 74.26 मिलियन भेड़, 148.88 मिलियन बकरियां, 9.06 मिलियन सूअर और लगभग 851.81 मिलियन मुर्गियां हैं।

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विवि के विज्ञानी पहली बार बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान के जरिए करेंगे शोध

प्रदेशभर की बकरियों को मिलेगी पहचान

जबलपुर। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में लगभग एक करोड़ 10 लाख बकरियां हैं, लेकिन न तो इनकी नस्लों को लेकर प्रदेश में कोई शोध हुआ, न ही क्षेत्र विशेष और खासियत के आधार पर इन्हें अब तक पहचान मिल सकी है। अब यह काम नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के विज्ञानिक करने जा रहे हैं। वे बकरियों पर शोध कर उनकी खासियत और उपयोगिता के आधार पर नस्लों का विभाजन करेंगे। इतना ही नहीं प्रदेश की सीमा से लगे अन्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में मिलने वाली बकरियों की प्रजातियों की खूबियों को मध्य प्रदेश की बकरियों में लाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान भी कराया जाएगा।

नेशनल लाइव स्टाक मिशन के तहत प्रोजेक्ट मिला- दरअसल वेटरनरी विश्वविद्यालय के मादा पशु रोग एवं प्रसूति विभाग को केंद्र सरकार के नेशनल लाइव स्टाक मिशन के तहत यह काम करने के लिए प्रोजेक्ट मिला है। इसमें उन्हें न सिर्फ प्रदेश की बकरियों की नस्लों का पहचान दिलाना है, बल्कि प्रयोगशाला तैयार कर उसमें मध्य प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों में मिलने वाली बकरे की प्रजातियों के सीमेन को संरक्षित भी करना है।

कृत्रिम गर्भाधान के जरिए प्रजातियों को विकसित किया जाएगा

जबलपुर के नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.एसपी तिवारी बोले-वेटरनरी विश्वविद्यालय पहली बार बकरी की प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन पर काम करने शोध करेंगे। इसके लिए पशुमादा रोग एवं प्रसूति विभाग को नेशनल लाइव स्टाक मिशन के तहत प्रोजेक्ट मिला है। इसके जरिए बकरे के सीमेन को संरक्षित करने का काम होगा। साथ ही कृत्रिम गर्भाधान के जरिए बकरियों की प्रजातियों को विकसित किया जाएगा।

पूरे प्रोजेक्ट पर एक नजर

वेटरनरी विवि का पहली बार बकरी की नस्ल बढ़ाने के लिए शोध कार्य करने प्रोजेक्ट मिला है। इसके लिए नेशनल लाइव स्टाक मिशन के तहत सवा दो करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। तीन साल के भीतर पशु विज्ञानिकों को इस शोध के परिणाम सामने लाने होंगे। इसके लिए अन्य वेटरनर विवि और वहां के विज्ञानिकों की मदद भी ली जाएगी।

बकरे की तीन नस्लों पर पहले होगा काम

प्रदेश की बकरी की नस्ल में सुधार करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा, लेकिन इसके लिए मध्यप्रदेश में बकरे के सीमेन को निकालने और संरक्षित रखने के लिए न तो कोई प्रयोगशाला और न ही कोई बैंक है। इस प्रोजेक्ट के जरिए पशु विज्ञानिक मध्यप्रदेश और इसकी सीमा से लगे आसपास के प्रदेशों के बकरे के सीमेन को संरक्षित कर बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान के जरिए स्ल सुधारेंगे। पहले चरण में विवि शोध के जरिए बकरे की खास नस्ल के सीमेन के लिए विश्वविद्यालय बकरे भी खरीदेंगा। वर्तमान में विवि के आमानाला स्थित बकरी फार्म में दो प्रजातियों के बकरे हैं। इसमें राजस्थान के सोही नस्ल और माथुरा की बरबरी नस्ल है। इसके बाद इटावा की जमुनापारी नस्ल पर भी काम होगा।

शोध में होगा यह काम

वेटरनरी महाविद्यालय जबलपुर के मादा पशु रोग एवं प्रसूति विभाग के विभागाध्यक्ष डा.एसएन शुक्ला बताते हैं कि मध्य प्रदेश में आज लगभग एक करोड़ से ज्यादा बकरियां हैं, लेकिन इनकी न तो कोई क्षेत्र विशेष और खासियत के आधार पर नस्लें हैं और न ही इसे बढ़ाने व संरक्षित करने के लिए कोई शोध हुआ है। वेटरनरी विज्ञानी की मदद से पहली बार हम यह काम करेंगे। इस शोध के जरिए उन्नत किस्म के बकरे का प्रजनन पर अध्ययन कर उनकी नस्ल का बढ़ाने का काम करेंगे। शोध के जरिए मध्य प्रदेश में क्षेत्र और खासियत के आधार पर बकरा-बकरी की नस्ल को पहचान दिलाने का काम होगा। वेटरनरी विश्वविद्यालय पहली बार बकरी में कृत्रिम गर्भाधान कर बकरे और बकरी की उन्नत नस्लों को तैयार करेंगे।

प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री ने सहकारी कांग्रेस को संबोधित किया

को-ऑपरेटिव में खत्म करें कैश का लेनदेनः प्रधानमंत्री मोदी

» आजादी के अमृत महोत्सव में हर जिले में बनाएं 75 अमृत सरोवर

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली में सहकारी कांग्रेस को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने देश में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने पर बल दिया। संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के जितने भी मिशन हैं, उनको सफल बनाने में मुझे सहकारिता के सामर्थ्य में मुझे कोई संदेह नहीं है। सहकारिता ने आजादी के आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने सहकारिता सेक्टर से एक अपील की। उन्होंने कहा कि इस सेक्टर को आने वाले समय में सभी ट्रांजैक्शन में कैश को खत्म करना चाहिए।

को-ऑपरेटिव सोसाइटी के डिजिटलीकरण के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आप (को-ऑपरेटिव सोसाइटी) मेरा एक काम कर दीजिए। डिजिटलाइज कीजिए। सभी ट्रांजैक्शन से कैश को खत्म करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, आज भारत की दुनिया में पहचान अपने डिजिटल लेनदेन के लिए होती है। ऐसे में सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों को भी इसमें अग्रणी रहना होगा।

अमृत सरोवर बनाने पर बल दिया

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश में अमृत सरोवर बनाने पर बल दिया। उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया कि देश में अब तक कितने अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने आवाह्न किया है कि आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएं। एक वर्ष से भी कम समय में करीब 60 हजार अमृत सरोवर देश भर में बनाए जा चुके हैं।

सहकारिता को कॉर्पोरेट सुविधा

प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में कहा, आज को-ऑपरेटिव को वैसी ही सुविधाएं, वैसे ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जैसे कार्पोरेट सेक्टर को मिलते हैं। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। हमारी सरकार ने सहकारी बैंकों को भी मजबूती दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई, तो हमनें सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। हमने पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया।

केंद्र की भंडारण योजना

देश में अनाज उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए भंडारण की सुविधा बहुत ही कम है। इस सुविधा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में हम जितना अनाज पैदा करते उसका 50 परसेंट से भी कम हम स्टोर कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना लेकर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीते अनेक दशकों में देश में करीब 1,400 लाख टन से अधिक की भंडारण क्षमता हमारे पास है। आने वाले पांच वर्षों में लगभग 700 लाख टन की नई भण्डारण क्षमता बनाने का हमारा संकल्प है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है, जो देश के किसानों का सामर्थ्य बढ़ाएगा, गांवों में नए रोजगार बनाएगा। पीएम मोदी ने कहा, एक प्रमुख विषय भंडारण का भी है। अनाज के भंडारण की सुविधा की कमी से लंबे समय तक हमारी खाद्य सुरक्षा और हमारे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)